भारतीय वैश्विक परिषद

सप्रू हाउस

****

'बांग्लादेश की वर्तमान अस्थिरता
इतिहास को फिर से लिखना या अप्रत्याशित भविष्य की रूपरेखा तैयार करना?'

विषय पर

आईसीडब्ल्यूए की पैनल चर्चा

14 **फरवरी** 2025

ध्रुबज्योति भट्टाचार्य: आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया अपने फोन को साइलेंट मोड पर कर लें। नमस्कार। माननीयों, देवियों और सज्जनों, भारतीय वैश्विक परिषद में आज होने वाली इस पैनल चर्चा में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। आज की चर्चा का विषय है- *बांग्लादेश की वर्तमान अस्थिरता, इतिहास को फिर से लिखना या अप्रत्याशित भविष्य की रूपरेखा तैयार करना*? आज दोपहर हो रहे इस कार्यक्रम की शुरुआत आईसीडब्ल्यूए की अपर सचिव सुश्री नूतन कपूर महावर के स्वागत भाषण से करेंगे। पैनल चर्चा की अध्यक्षता बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त रहीं राजदूत वीना सीकरी करेंगी। चर्चा के बाद एक संक्षिप्त प्रश्नोत्तर सत्र भी होगा जिसका संचालन अध्यक्ष महोदया करेंगीं। अब मैं आईसीडब्ल्यूए की अपर सचिव सुश्री नूतन कपूर महावर से अनुरोध करता हूँ कि कृपया वे अपना स्वागत भाषण दें।

नूतन कपूर महावर: माननीय अध्यक्ष महोदया और विशेषज्ञों, राजनयिक दल के सदस्यों, छात्रों और मित्रों!

साल 1971 में खूनी मुक्ति संग्राम, जिस संग्राम में यह पश्चिमी पाकिस्तान के दमनकारी और नरसंहारकारी शासन से सफलतापूर्वक अलग हो गया, के बाद, बांग्लादेश ने अपने नागरिकों को पूर्ण सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार प्रदान करने की आकांक्षा के साथ स्वयं को एक अलग पहचान देने के लिए जन्म लिया।

अकाल, बाढ़ और महाचक्रवातों जैसी लगातार आई प्राकृतिक आपदाओं, गंभीर राजनीतिक अस्थिरता- सत्तावादी शासन, राजनीतिक हत्याएं और तख्तापलट, सैन्य एवं अब हाइब्रिड शासन व्यवस्थाओं और निराशाजनक सामाजिक-आर्थिक मापदंडों से त्रस्त बांग्लादेश के लोग अभी भी वादा किए गए सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि की बाट जोह रहे हैं।

सेना और न्यायपालिका जैसी राष्ट्रीय संस्थाएं बांग्लादेश में घरेलू और विदेश नीति निर्माण में बड़ी भूमिका निभाती है। साल 1971 से या तो आवामी लीग या बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सत्ता में रही है। बीच- बीच में सैन्य शासन या अंतरिम सरकारें आती रही हैं। निर्वाचित सरकारों की अक्सर होने वाली बर्खास्तगी बांग्लादेश की राजनीतिक संस्कृति की बहुत ही बुरी तस्वीर पेश करती है- इसमें गंभीर राजनीतिक दमन, हिंसक विरोध, हड़ताल, अपवित्रता, लूट और आगजनी, निजी और सार्वजनिक संपत्तियों का विध्वंस, राजनीतिक कैद और हत्याएं शामिल हैं। जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था, हर शासन परिवर्तन के बाद इतिहास को फिर से लिखने का प्रयास किया गया है और यही वह बात है जो एक बार फिर से वर्तमान बांग्लादेश में देखी जा रही है।

बांग्लादेश की अंतर्निहित राजनीतिक संस्कृति पाकिस्तान से बहुत अलग नहीं है। एक चौथाई सदी से जुड़वां होने के कारण, उनका राजनीतिक डीएनए एक जैसा ही है। उदाहरण के लिए, बांग्लादेश की सेना ने दशकों से पाकिस्तान की सेना के साथ जो सौहार्द एवं आत्मीयता दिखाई है, वह गैर- राजनीतिक भारतीय सेना और अत्यधिक राजनीतिक बांग्लादेशी सेना के बीच के संबंधों से कहीं अधिक गहरा है। इसी तरह, इस्लामी कट्टरपंथी समूहों को बांग्लादेश में उपजाऊ ज़मीन मिली है और उन्होंने अपने पाकिस्तानी समकक्षों के साथ घनिष्ठ संबंधों का लाभ उठाया है, यह आज भी जारी है। वर्ष 1971 ने भले ही दोनों को विभाजित कर दिया हो लेकिन वही अस्वस्थता उनकी राजनीति को निर्धारित करती है।

वर्तमान मुख्य सलाहकार यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार का गठन सामान्य स्थिति बहाल होने के बाद की गई थी ताकि नए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जा सकें। यह देखते हुए कि आवामी लीग सरकार की देखरेख में जनवरी 2024 के चुनाव में कथित तौर पर धांधली हुई थी, वर्तमान अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद से अगले चुनाव से पहले चुनावी सुधारों की मांग की जा रही है। हालांकि, छात्र समुदाय और विभिन्न राजनीतिक गुटों एवं कट्टरपंथी तत्वों को शांत करने के लिए इस संबंध में कार्रवाई करने की बजाय सेना द्वारा समर्थित अंतरिम सरकार सक्रिए रूप से ध्रुवीकरण के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। देश को "अस्थिर" करने की इच्छा रखने वालों पर कथित रूप से लक्षित "ऑपरेशन डेविल हंट" जैसे छापे मारने के नाम पर अंतरिम सरकार सीधे- सीधे लोकतंत्र के समर्थकों को निशाना बना रही है और उन्हें गिरफ्तार कर रही है जिससे हाइब्रिड शासन की विश्वसनीयता गंभीर रूप से कमज़ोर हो रही है।

अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा भी ठप्प पड़ा हुआ है। पिछले छह महीनों में बांग्लादेश में अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में हड़तालें देखी गई हैं जिसमें कपड़ा और परिवहन जैसे निर्यातोन्मुख क्षेत्र शामिल हैं और अक्सर राजमार्गों की नाकेबंदी भी देखी गई है।

असहिष्णुता अंतर- धार्मिक और अंतर- जातीय संबंधों में व्याप्त हो गई है। हालांकि अंतरिम सरकार और स्थानीय मीडिया द्वारा इसे कम करके आंका गया है, लेकिन धार्मिक एवं जातीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ असहिष्णुता और हिंसा के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अंतरराष्ट्रीय कट्टरपंथी इस्लामी समूहों की उपस्थिति में भी वृद्धि देखी जा रही है। जबकि मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की स्वतंत्रता का दमन जनता के बीच निराशा को बढ़ावा दे रहा है, स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख अल्पसंख्यकों से संबंधित लोगों की हत्याएं, जैसे कि हाल ही में अमेरिकी नागरिक समाज संगठन 'सेव द चिल्ड्रेन' के प्रोजेक्ट डायरेक्टर उत्पल रॉय की हत्या, फिर भी व्यापक ध्यान आकर्षित कर रही हैं।

इतिहास को फिर से लिखने और सामाजिक ताने- बाने को बदलने के हिंसक प्रयास करते हुए, सेना द्वारा समर्थित यूनुस की अंतरिम सरकार ने पिछली आवामी लीग सरकार द्वारा भारत के साथ बनाए गए सहयोग एवं साझेदारी के स्तर को समायोजित करने एवं जांचने का विकल्प भी चुना है। यूनुस रक्षा और सैन्य क्षेत्रों समेत पाकिस्तान एवं चीन जैसे देशों के साथ नए रास्ते तलाशने और साझेदारी को मजबूत करने का विकल्प अपना रहे हैं। बेशक, पिछले अमेरिकी प्रशासन और यूनुस के बीच की निकटता पर मीडिया में व्यापक रूप से चर्चा हुई है; और नए अमेरिकी प्रशासन के तहत गतिशीलता को देखा जाना बाकी है। बांग्लादेश- म्यांमार अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थिति के मामले में बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता के प्रभाव, विशेष रूप से अराकान सेना के बढ़ते प्रभाव के साथ, की भी सावधानीपूर्वक पड़ताल की जानी चाहिए।

भारत के लिए, बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण पड़ोसी बना हुआ है, चाहे सत्ता में कोई भी सरकार हो और भारत को अपने राष्ट्रीय और सुरक्षा हितों को कम किए बिना विश्वास को फिर से बनाने के लिए काम करना होगा। हालांकि यह बांग्लादेश के आंतरिक मामलों का सम्मान करता है लेकिन विशेष रूप से 4000 किलोमीटर से अधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कड़ी नज़र रखने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता आमतौर पर मानव, हथियार, नशीली दवाओं और पशु तस्करी एवं घुसपैठ जैसे आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देती हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सीमा के दोनों ओर के लोगों की भलाई सर्वोपरि है।

मैं, आज हमारे पैनल में शामिल प्रतिष्ठित विशेषज्ञों का स्वागत करती हूँ। मुझे विश्वास है कि वे इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और अपने विचार हमसे साझा करेंगे। मैं एक विचारोत्तेजक एवं जीवंत चर्चा की आशा करती हूँ। शुभकामनाएं।

ध्रुबज्योति भट्टाचार्य: धन्यवाद महोदया। अब मैं राजदूत सीकरी से अनुरोध करता हूँ कि अपना भाषण दें और कार्यवाही का संचालन करें। धन्यवाद महोदया।

वीणा सीकरी: धन्यवाद। मैं आईसीडब्ल्यूए और श्रीमती नूतन कपूर महावर को इस चर्चा को सही समय पर आयोजित करने के लिए बधाई देना चाहती हूँ। मुझे याद है कि लगभग चार महीने पहले आईसीडब्ल्यूए में एसोसिएशन ऑफ इंडियन डिप्लोमैट्स के तत्वाधान में एक चर्चा हुई थी, और अब छह माह के बाद, स्थिति की समीक्षा का बिल्कुल सही समय है। इसलिए ऐसा करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं प्रोफेसर संजय भारद्वाज और डॉ. स्मृति पटनायक को धन्यवाद देना चाहूँगी। वर्चुअल प्लेटफॉर्म ज़ूम पर हमारे साथ सुश्री सोहिनी बोस भी होंगी। मैं कहना चाहती हूँ कि छह महीने का समय आकलन के लिए अच्छा समय है। आइए देखें कि बीते छह महीनों में, जब से प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार सत्ता में आई, बांग्लादेश में क्या हो रहा है।

दो या तीन बातें मेरे दिमाग में आती हैं। मुझे लगता है कि अंतरिम शासन की संवैधानिक वैधता के बारे में बांग्लादेश में भावनाएं तेज़ी से बढ़ रही हैं। यह भावना इसलिए आई है क्योंकि मेरे विचार से शासन, मुख्य सलाहकार और दूसरे सलाहकारों ने बांग्लादेश के संविधान के तहत शपथ ली थी लेकिन उस संविधान में अंतरिम सरकार के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए, इस अर्थ में, तत्काल अर्थ में, सरकार की कोई वैधता नहीं है। लेकिन आप देखें कि, हाँ, न्यायाधीशों का एक नया समूह है, यह भी बांग्लादेश के लोगों के बीच उठने वाले मुद्दों में से एक था। भीड़ के न्याय को सही ठहराना, पुराने न्यायाधीशों को घेरने वाली भीड़तंत्र, उन्हें इस्तीफा देने के लिए मज़बूर करना।

इसलिए बिना किसी उचित प्रक्रिया के, नए लोगों की एक श्रृंखला आ गई है, चाहे वह विश्वविद्यालयों में कुलपित हों या फिर न्यायाधीश। इसलिए, इन न्यायाधीशों ने वास्तव में 15वें संशोधन की समीक्षा की है जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल में किया गया था। उन्होंने 15वें संशोधन के कुछ हिस्से के संचालन को रोक दिया है, जिसने कार्यवाहक सरकार को समाप्त कर दिया था। लेकिन अगर आप कार्यवाहक सरकार को देखें, भले ही आप

इस पद्धति पर विचार करें, चाहे वह संविधान में वापस हो या नहीं, उस कार्यवाहक सरकार ने केवल- पहला, कानून और व्यवस्था को देखने और दूसरा- 90 दिनों के भीतर चुनाव कराने की अनुमति दी थी।

तीसरा, यह एक तटस्थ, गैर- पार्टी सरकार, कार्यवाहक सरकार होने का आदेश था। इसलिए इनमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ, एक भी आवश्यकता पूरी नहीं हुई। 90 दिनों से ज्यादा बीत चुके हैं, उससे दोगुना बीत चुका है। मुझे लगता है कि यह बहुत स्पष्ट है कि इस्लामिस्ट संगठनों के लोग अंतरिम सरकार में सलाहकार के रूप में सदस्य हैं, और वे नियंत्रण भी करते हैं, जमात- ए- इस्लामी को स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण रखने और वास्तव में क्या होने वाला है, इसका मार्गदर्शन करने के लिए जाना जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि जब आप जमात- ए- इस्लामी को प्रभारी के रूप में देखते हैं, तो आप - *इतिहास को फिर से लिखा जाना*, शीर्षक को बहुत उपयुक्त पाते हैं क्योंकि जमात- ए- इस्लामी 1971 से पहले की स्थिति में लौटने का प्रयास कर रहा है।

यह वे स्वयं कह रहे हैं क्योंकि जब से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, हम जमात- ए- इस्लामी और पाकिस्तान के बयानों को देख रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि हमें 1971 की समीक्षा करनी होगी, हमें 1971 के अनसुलझे मुद्दों को देखना होगा इसलिए आप आज उन्हीं ताकतों के मेल को देख रहे हैं जो 1971 में हार गए थे, चाहे वे पाकिस्तान हो, चाहे जमात- ए- इस्लामी, चाहे रजाकार हो। इसलिए वे ताकतें जो आज प्रभारी हैं वे निश्चित रूप से इतिहास को फिर से लिखने के प्रयास में सबसे आगे हैं।

लेकिन क्या यह लोगों को स्वीकार्य है? क्या कानून और व्यवस्था नियंत्रण में है? निश्चित रूप से बांग्लादेश में कानून और व्यवस्था एक गंभीर समस्या बनी हुई है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मारे गए और भले ही सेना को मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकार दिए गए हों लेकिन वे वास्तव में खुद को इन सब में शामिल नहीं कर रहा हैं। उन्हें इस बात का डर है कि यदि वे इन सब में शामिल हुए तो संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों का हिस्सा नहीं रह पाएंगे।

इसलिए, मैं समझता हूँ कि यह पूरी तरह से एक ऐसी स्थिति है जिसने देश की अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया है और अर्थव्यवस्था के बीते वर्ष की तुलना में आधी या आधी से भी कम दर से बढ़ने की उम्मीद है, इसलिए इसका असर नौकरियों पर पड़ेगा, इससे अत्यधिक मुद्रास्फीति पैदा होगी, इससे निवेश में कमी आएगी, बांग्लादेश में नए निवेश में कमी आएगी, इससे बड़ी संख्या में कारखाने बंद हो रहे हैं क्योंकि श्रमिकों में असंतोष है क्योंकि श्रमिक वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इससे भ्रम की स्थिति भी पैदा हुई है क्योंकि बांग्लादेश की

कुछ सबसे बड़ी कंपनियां रिसीवरशिप में हैं और उनके पास पैसा नहीं है इसलिए उनके पिछले श्रमिकों को हज़ारों, हज़ारों की संख्या में नौकरी से निकाला जा रहा है क्योंकि यह एक बहुत बड़ी कंपनी है।

यह सब बहुत भ्रम पैदा कर रहा है और मुझे निश्चित रूप से उम्मीद है कि हमारे पैनल के सदस्य इस भ्रम की स्थित पर प्रकाश डाल पाएंगे और फिर शायद इसके अंत में, मैं एक बार फिर संक्षेप में बताऊंगी कि हमने क्या बात की है। इन कुछ शब्दों के साथ, मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज़ के प्रोफेसर संजय भारद्वाज से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आएं और अपने विचार हमसे साझा करें। समय की थोड़ी कमी है। हम आपको 10 मिनट का समय दे पाएंगे।

संजय भारद्वाज: धन्यवाद मैडम। राजदूत वीणा सीकरी महोदया धन्यवाद। मैं आईसीडब्ल्यूए, विशेष रूप से अपर सचिव श्रीमती नूतन कपूर महावर जी को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने यह अवसर दिया। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की, जो नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और विद्वानों के बीच कम- से- कम पिछले छह, सात महीनों से चर्चा में था। यह... मैं कह सकता हूँ कि भारत के पड़ोस में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम हुआ, क्योंकि यहाँ भारत ने राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक रूप से बहुत निवेश किया था।

हम भारत की प्रमुख परियोजनाओं, प्रमुख नीतियों जैसे एक्ट- ईस्ट नीति, उत्तर- पूर्व से जुड़ना, बंगाल की खाड़ी की परियोजनाओं से जुड़ना और विकास परियोजनाओं के लिए विभिन्न कर्ताओं को आमंत्रित करना, के साथ बहुत समावेशी तरीके से जुड़ने और खेती करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यह बांग्लादेशियों के लिए अच्छा नहीं रहा और कई बार हमें आलोचना का भी सामना करना पड़ा। मैं उत्तर- पूर्व में एक सम्मलन में था और एक प्रोफेसर ने कहा कि आप बस बर्बाद कर रहे हैं और बांग्लादेश में पैसा डाल रहे हैं, वे किसी के प्रति कृतघ्न हैं। ये शब्द थे, फिर मैंने कहा नहीं, नहीं, नहीं, हमें बांग्लादेश में निवेश करना है, उसे विकसित करना है और मुझे लगता है कि भारत के हितों की सेवा के लिए भू- आर्थिक और भू- रणनीतिक रूप से यह बहुत महत्वपूर्ण है।

मैंने अपनी प्रस्तुति को तीन भागों में विभाजित किया है। एक, निश्चित रूप से, मैं आंतरिक चर्चा के बारे में चर्चा करूँगा, बांग्लादेश किसका सामना कर रहा है। दूसरा, इन मुद्दों, इन घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय गतिशीलता क्या है, और हाल के दिनों में किस तरह से क्षेत्र- बाह्य शक्तियों की भागीदारी देखी गई है। ये सर्वविदित तथ्य है कि बांग्लादेश में राजनीति और समाज दो ताकतों के बीच विभाजित है। एक है जातीय- सांस्कृतिक ताकतें, मैं कह सकता हूँ कि ये जातीय- सांस्कृतिक ताकतें, उनका मानना है कि वे 1971 की भावना

का प्रतिनिधित्व करती है। वह भावना बंगाली राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और समाजवाद की समावेशिता पर आधारित है। ये मूल सिद्धांत थे जिन्हें बाद में मुज़ीबवाद के रूप में जाना गया। उन्हें मुक्ति- समर्थक युद्ध बलों के रूप में जाना जाता है। वे प्रगतिशील थे, वे सांस्कृतिक गतिशीलता या समावेशिता लाने के लिए काम कर रहे थे जो बंगाली संस्कृति में वर्षों से थी।

इस बात का विरोध उन ताकतों ने किया है जो जातीय- धार्मिक निर्माण में विश्वास करती हैं। मैं कहूँगा कि उन्हें 1947 की ताकतों के रूप में जाना जाता है। वे पुराने मुस्लिम लीग के लोग हैं। वे इस्लामी राष्ट्रवादी निर्माण में विश्वास करते हैं और उस समय पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली और अरबी लिपि के बजाय उर्दू को राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करके इस तरह की पहचान थोपना चाहते थे और ये सभी प्रयास किए गए थे। इन ताकतों में बांग्लादेश में स्थित कट्टरपंथी इस्लामी ताकतें शामिल हैं। मैं कहूँगा कि जमात- ए- इस्लाम, जिसमें इस्लामी छात्र शिबिर, अल- बद्र, रजाकर, अल- शम्स थे, ये सभी लोग और जमात- ए- इस्लामी नेतृत्व में शामिल हो गया और इन ताकतों ने 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति या निर्माण का विरोध किया।

इसलिए ये द्वंद्व और विवाद चलते रहे और 1975 में जब बंगबंधु मुजीबुर रहमान की हत्या हुई तो उन्होंने इतिहास बदलने की कोशिश की। उन्होंने इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश की क्योंकि विषय भी बांग्लादेश के इतिहास को फिर से लिखने के बारे में बात कर रहा है। आज भी, बांग्लादेश में संविधान बदलने, इतिहास को फिर से लिखने, नायकों को बदलने, प्रतीकों को बदलने, छुट्टियों को बदलने, राष्ट्रपिता को बदलने के लिए गहन चर्चा चल रही है और वे जश्न मना रहे हैं... जिन्ना की जयंती मनाई गई और उर्दू भाषा में उन्होंने वह भाषा इस्तेमाल की जिसका इस्तेमाल उन्होंने 1947 की ताकतों को बांग्लादेश में वापस लाने के लिए किया।

साल 1975 में बंगबंधु की हत्या के बाद भी संविधान को बदलने की कोशिश की गई। संविधान और खासकर अगर मैं कहूँ कि आज़ादी के संघर्ष की जगह मुक्ति संग्राम ने ले ली, मुक्ति संग्राम के योगदान को उजागर किया गया। बंगाली राष्ट्रवाद की जगह बांग्लादेशी राष्ट्रवाद ने ले ली और इस्लाम उस बांग्लादेशी राष्ट्रवाद का मूल था। धर्मनिरपेक्षता की जगह सर्वशक्तिमान अल्लाह ने ले ली या आप कह सकते हैं कि बाद में इस्लाम को बांग्लादेश का राजकीय धर्म घोषित कर दिया गया। प्रस्तावना के शीर्ष पर बिस्मिल्लाह- उर- रहमान- उर- रहीम लिखा है।

आप देख सकते हैं कि 1975 से 1990 के बीच मुज़ीब के बाद के दौर में बांग्लादेश में इतिहास को बदलने और फिर से लिखने की कोशिश की गई और ये संघर्ष जारी रहे। मुझे लगता है कि किसी तरह, बांग्लादेश, वे बार-बार वापस आते हैं। वे 1989 में वापस आए, फिर वे 2007 में वापस आए और 2008 के बाद, मुझे लगता है कि 1971 की भावना को फिर से स्थापित करने के लिए 2008 के चुनाव में शेख हसीना का नारा और चुनाव घोषणापत्र क्या था। 1971 की भावना क्या थी? मैंने बंगाली सांस्कृतिक लोकाचार, मूल्यों, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और इन सब के बारे में बात की है। हालांकि, वैधता को स्वीकार करना और बनाए रखने के लिए उन्होंने बांग्लादेश में लोकाचार एवं मूल्यों को और अधिक विभाजित करने की कोशिश की, विशेष रूप से लक्ष्यों और मूल्यों के बीच विभाजन एवं लक्ष्यों को आर्थिक प्रदर्शन से जोड़ा गया है। उन्होंने आर्थिक क्षेत्रों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है जिसके कारण बांग्लादेश विकासशील देशों की श्रेणी में आ रहा है।

लोगों के मूल्यों के बजाय, वे अधिक समावेशी भागीदारी वाले चुनाव और ऐसी ही अन्य चीजें मांग रहे थे। इसने बांग्लादेश में समानता और स्वतंत्रता के बीच की खाई को बढ़ाया है। डिजिटल सुरक्षा अधिनियम जैसे अधिनियमों की व्यापक रूप से आलोचना की गई है। लेकिन मैं कहूँगा कि सत्ता में रहते हुए उन्होंने कई बड़ी गलतियां भी की हैं। वह समावेशी मूल्यों और लोकाचार को बनाए रखने में बहुत अच्छा काम कर रही थीं। वह देश में कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा करने वाली कट्टरपंथी इस्लामी ताकतों को दबाने की कोशिश कर रही थीं और देश के लिए विकास और निवेश लाने में लगी थीं। लेकिन उन्होंने जो किया वह यह कि जमात- ए- इस्लाम और कट्टरपंथी ताकतों, 1917 की ताकतों को बेअसर करने के लिए, उन्होंने हिफ़ाजत- ए- इस्लाम का समर्थन करके और उससे समर्थन प्राप्त करके एक वैकल्पिक विमर्श बनाने की कोशिश की है। हिफाजत- ए- इस्लाम ने वास्तव में किसी तरह इस्लामी लोकाचार और मूल्यों को बरकरार रखा है। यह 15वें संविधान संशोधन के दौरान बहुत हद तक परिलक्षित हुआ कि इस्लाम बांग्लादेश का राजकीय धर्म बना रहेगा।

यह कहा गया कि धर्मनिरपेक्षता और इस्लाम एक साथ मौजूद हैं। यह एक व्यावहारिक नज़रिया था जो देखा गया था। आगे जो देखा गया वह यह था कि उन्होंने किसी प्रकार लोकतांत्रिक साख के साथ समझौता किया। शायद ही कोई स्थानीय निकाय चुनाव, उप- जिला चुनाव और इस तरह के अन्य चुनाव हुए हों। बांग्लादेश में लोगों को मतदान नहीं करना पड़ता। संसदीय चुनावों में शीर्ष स्तर पर उनके आयोजन को लेकर भी बार- बार सवाल उठाए गए हैं। भ्रष्टाचार, भाई- भतीजावाद और सबसे महत्वपूर्ण कारक छात्र लीग की भूमिका थी, आवामी लीग की छात्र शाखा कार्यान्वयन में बहुत अधिक आक्रामक थी या चीजों को बदलने की कोशिश कर रही थी। मुझे लगता है कि यह किसी तरह उसके खिलाफ गया। लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था।

यह दो मुद्दों से पुष्ट होता है। एक है कोटा का मुद्दा जो सर्वविदित है, स्वतंत्रता सेनानियों और अन्य लोगों के लिए आरक्षण। फिर बाद में बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और निश्चित रूप से, तात्कालिक कारणों से प्रदर्शनकारियों, छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। ये मुद्दे थे। यह प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने में सहायक बन गया। इसे किसी तरह लेबल किया गया है कि पाकिस्तान समर्थक ताकतें छात्रों के साथ भेदभाव और इस प्रकार की अन्य चीजों के खिलाफ सक्रिए रूप से शामिल थीं। भारत के खिलाफ लोगों का गुस्सा था। लेकिन भारत हमेशा बहुत मजबूत रहेगा। वास्तव में, आप कह सकते हैं कि पिछले बहुत वर्षों में भारत ने बांग्लादेश में आर्थिक रूप से निवेश किया है, जहाँ पाकिस्तान ने वैचारिक रूप से या आप कह सकते हैं, निवेश समाज के कट्टपंथीकरण की दिशा में किया है। फिर यह जारी रहा, डीप स्टेट की मौजूदगी की अब बार- बार रिपोर्ट की गई है कि जमात-ए- इस्लाम और कट्टरपंथी ताकतें पाकिस्तान की कट्टरपंथी ताकतों के साथ मिलकर काम कर रही थीं।

आखिरी बात जो मैं कहना चाहूँगा, वह यह है कि अगस्त में, आप 1971 की सांठ-गांठ देख सकते हैं जैसा कि राजदूत सीकरी ने भी संकेत दिया है, कि कट्टरपंथियों, पाकिस्तान, अमेरिकियों और चीनियों के बीच सांठ-गांठ काफी सक्रिए थी, परलक्षित भी हुई। चीनी, वे चुप रहे, लेकिन आप जानते हैं, वे बांग्लादेश के समाज में भी काम कर रहे थे, संकेत स्पष्ट थे। ग्रेज़ोन में ऐसी रिपोर्ट भी हैं जिनसे आप देख सकते हैं कि कैसे लोगों या नागरिक समाज के लोगों का इस्तेमाल किया गया था और ऐसे सबूत और रिपोर्ट भी हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका बांग्लादेश में जमात- ए- इस्लाम के साथ सहयोग कर रहे थे।

अमेरिकियों ने, निश्चित रूप से, अमेरिकियों ने अपनी सभी रणनीतिक बातों को, मेरा मतलब है, लोकतंत्र और मानवाधिकारों से जोड़ दिया था और ये सभी मुद्दे उनके रणनीतिक हितों से जुड़े हुए हैं। अमेरिकियों की बंगाल की खाड़ी में गहरी रणनीतिक रुचि थी और वे लंबे समय से बंगाल की खाड़ी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रहे थे। साल 1972 में उन्होंने एक आधार मांगा। साल 1954-55 में हालांकि वे इसका विरोध कर रहे थे। वर्ष 1998 में, उन्होंने एसओएफए (SOFA) समझौते के लिए कहा था, और फिर, वे थे, एक गोरा सेंट मार्टिन द्वीप में बेस मांग रहा है, उस तरह का, इसलिए वे चाहते थे, शायद अमेरिकियों को विश्वास नहीं था कि भारत और दूसरी ताकतें क्या कर रही हैं। वे आशंकित थे, बंगाल की खाड़ी में बढ़ती चीनी उपस्थिति, विशेष रूप से म्यांमार में, जैसा कि मैडम महावर ने सही ढंग से बताया, चीन- म्यांमार आर्थिक गलियारे के बारे में, जिस

तरह से चीनी सैन्य शासक गुट का समर्थन कर रहे हैं, जिस तरह से अराकान सेना और वे अपनी उपस्थिति बना रहे हैं, मुझे लगता है कि किसी तरह यह लोगों से संबद्ध है।

आखिरी बात, आज बांग्लादेश में क्या चल रहा है? संवैधानिक संकट है। इस सरकार, अंतरिम सरकार के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। कार्यवाहक सरकार का प्रावधान था, लेकिन 15वें संविधान संशोधन में इसे हटा दिया गया। यह असंवैधानिक सरकार है, पहला संकट। दूसरा संकट वैधता का संकट है, कि, यह सरकार वैध नहीं है और अंतरिम सरकार के किसी भी व्यक्ति, सलाहकार को किसी भी तरह का जन समर्थन नहीं मिल रहा है, सिवाय, आप कह सकते हैं, भेदभाव के खिलाफ छात्रों के। उन्हें युवा पीढ़ी का समर्थन प्राप्त है। वे रोजगार से निराश हैं और वे कानून और व्यवस्था, इस प्रकार की अन्य चीजों से निराश हैं।

राजनीतिक संकट हैं। राजनीतिक संकट इस अर्थ में है कि भेदभाव के खिलाफ एक विशेष छात्र की स्थिति है, उनके पास कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। वे एक राजनीतिक पार्टी बनाने के बारे में विचार कर रहे हैं। इसलिए राजनीतिक संकट है। केवल एक राजनीतिक पार्टी है, बीएनपी (BNP)। अंतरिम सरकार चुनाव में भाग लेने के लिए आवामी लीग को हटाने की कोशिश कर रही है। इसलिए एक राजनीतिक संकट है, और नेतृत्व का संकट है। अंतरिम सरकार में शामिल लोगों में से किसी को भी लोगों का नेतृत्व करने का कोई अनुभव नहीं है। वे 2001 से 2006 तक बीएनपी सरकार, बीएनपी जमात सरकार के दौरान यहाँ और वहाँ सरकार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं।

आखिरी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्वास की कमी है। विश्वास की कमी आवामी लीग एवं अंतरिम सरकार के बीच नहीं है। अब सत्तारूढ़ गठबंधन में भी विश्वास की कमी है। बीएनपी को जमात- ए- इस्लाम पर विश्वास नहीं है। जमात- ए- इस्लाम चुनाव नहीं चाहता है। बीएनपी जल्द चुनाव चाहती है। बीएनपी और जमात- ए- इस्लाम परंपरागत रूप से मोहम्मद यूनुस और वहां के लोगों के प्रतिद्वंद्वी रहे हैं। इसलिए देश में विश्वास की बहुत कमी है। यही मूल कारण है कि चुनाव में देरी हो रही है। वे सुधारों और ऐसी ही दूसरी चीजों की आशा कर रहे हैं।

मेरा कहना यह है कि, आखिरी बात जो मैं कहना चाहूँगा, मुझे लगता है कि ट्रम्प ने कल जो कहा कि भारत ध्यान रखेगा, मोदी ध्यान रखेगा, वह मुद्दा तो है, इस पर कोई प्रश्न पूछेगा तो मैं उस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। लेकिन मुद्दा यह है कि बांग्लादेशियों के पास अपना समाधान है। उन्होंने 1971 में प्रतिक्रिया की थी, आज़ाद

देश बने थे। उन्होंने 1989 के जामदानी क्रांति के जरिए प्रतिक्रिया की, लोकतंत्र को बहाल किया। उन्होंने 2007 में प्रतिक्रिया की और कार्यवाहक सरकार, सेना समर्थित कार्यवाहक सरकार को हटा दिया, जहाँ वे माइनस टू कूटनीति की आशा कर रहे थे। मुझे विश्वास है कि वे अगस्त में हुई अधूरी क्रांतियों को पूरा करने के लिए फिर से प्रतिक्रिया करेंगे। इसलिए बांग्लादेशी लोग, वे धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, प्रगतिशील ताकतों को सत्ता में बहाल करेंगे। बहुत- बहुत धन्यवाद।

वीना सीकरी: धन्यवाद। उन सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं को सामने लाने के लिए धन्यवाद। डॉ. स्मृति पटनायक, आपसे अनुरोध है कि आप अपनी प्रस्तुति दें।

स्मृति पटनायक: अध्यक्ष महोदया धन्यवाद। आईसीडब्ल्यूए, इस आमंत्रण के लिए आपका धन्यवाद। मैं तीन, चार बातों पर चर्चा करना चाहूँगी। मूल रूप से ये आंतरिक मुद्दे हैं। एक मुद्दा वह है जिसका उल्लेख मैडम ने भी किया था, अंतरिम शासन की संरचना। मैं वैधता के पक्ष पर विचार नहीं करना चाहती। जाहिर है, उन्होंने संविधान के तहत शपथ ली है, जिसे वे वर्तमान में सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आप अंतरिम शासन की संरचना को देखें, तो हम कुछ चीजें देख सकते हैं। कुछ छात्र नेता है जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

इसलिए उनकी राजनीतिक पहचान पर कई लोगों ने सवाल उठाए हैं। कुछ लोगों को मूल रूप से इस्लामिस्ट कहा गया है। क्योंकि अगर आप छात्र आंदोलन को देखें, तो इस्लामिस्टों ने बहुत प्रमुख भूमिका निभाई है, विशेष रूप से जमात- ए- इस्लामी ने। उन्होंने दावा किया है कि जुलाई- अगस्त क्रांति में, उनके 89 कार्यकर्ता मारे गए। मारे गए कार्यकर्ताओं में छात्र संगठन और पार्टी दोनों के कार्यकर्ता थे। अब, जब यह अंतरिम शासन आ गया है, तो यह स्पष्ट नहीं है कि चुनाव कब होंगे। शुरू में उन्होंने कहा था कि उन्हें चार साल लगेंगे। फिर सेना प्रमुख ने एक साक्षात्कार दिया और उन्होंने कहा कि शायद हम इसे दो साल में पूरा कर लेंगे। लेकिन अब सरकार ने कहा है कि इस साल के आखिर में चुनाव करवाने जा रही है।

लेकिन सवाल यह है कि क्या सुधार होने के बाद चुनाव होंगे या फिर सुधार को इंतजार करना होगा। इसलिए अब राजनीतिक दल चुनाव के रोडमैप को लेकर बहुत- बहुत विभाजित हैं। बीएनपी का रुख यह है कि वे चुनाव के लिए आवश्यक न्यूनतम सुधार कर सकते हैं और बड़े सुधारों को निर्वाचित सरकार पर छोड़ सकते हैं, जब भी वह सत्ता में आए। लेकिन जमात- ए- इस्लामी, बहुत दिलचस्प बात यह कह रही है कि अगर हम सुधार नहीं करेंगे और चुनाव नहीं कराएंगे, तो मुझे यह बहुत हास्यास्पद लगा कि सरकार चुनावी नरसंहार करने जा रही है।

इसलिए, उन्होंने यही शब्दावली कही, क्योंकि जमात जो तर्क दे रही है कि अगर कोई सुधार नहीं हुआ तो जुलाई-अगस्त क्रांति ने जिस प्रकार सरकार बनाई थी, उसी तरह की सरकार फिर से सत्ता में आने वाली है।

लेकिन अगर आप बांग्लादेश के इतिहास को देखें, जैसे, 2007-2008, जब सत्ता में तत्कालीन सैन्य समर्थित सरकार द्वारा बहुत सारे सुधार कार्य किए गए थे। जब आवामी लीग सत्ता में आई, तो ज्यादातर सुधार कार्यों को खारिज कर दिया गया या बंद कर दिया गया क्योंकि आप अध्यादेश के जरिए सुधार कर सकते हैं लेकिन एक बार संसद की बैठक होने के बाद, उन सुधारों को दो- तिहाई बहुमत से पारित करना होगा। इसलिए हमने उस समय देखा, मुझे लगता है कि 2007 और 2008 में सैन्य सरकार द्वारा लाए गए लगभग 90% सुधारों को सत्तारूढ़ राजनीतिक दल द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। तो इस बात की क्या गारंटी है कि सुधार होने के बाद, जो सरकार सत्ता में आएगी वह उन सुधारों को स्वीकार कर ही लेगी। लेकिन बीएनपी और जमात में बहुत बड़ा फर्क है।

कई लोगों का तर्क है कि शायद बीएनपी, जिसे एक ऐसी पार्टी के रूप में देखा या वर्णित किया जाता है जो सत्ता में वापसी का इंतज़ार कर रही है, जमात को वास्तव में स्वयं को संगठित करने एवं चुनाव लड़ने के लिए कुछ समय चाहिए। हालाँकि उन्हें कानूनी लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि यह एक राजनीतिक पार्टी के रूप में अपंजीकृत है। मामला, अपंजीकरण का मामला अभी भी अदालत में लंबित है। कोई निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन जिस प्रकार से अंतरिम शासन चल रहा है, मुझे लगता है कि जल्द ही उन्हें किसी भी मामले में पंजीकरण वापस मिल जाएगा। यदि वे संवैधानिक सुधार लागू करने जा रहे हैं, जिसमें धर्मनिरपेक्षता नहीं है, लेकिन बहुलवाद है, तो जमात का संविधान वास्तव में बांग्लादेश के संविधान से नहीं टकराएगा, जिस आधार पर जमात- ए- इस्लामी को अपंजीकृत किया गया था।

जब आप इतिहास को देखते हैं, मुझे तो यह बहुत दिलचस्प लगता है। कई लोग दूसरी आज़ादी या दूसरी मुक्ति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। हालाँकि, बांग्लादेश में बहुत से लोग कह रहे हैं कि इसे दूसरी मुक्ति नहीं कहा जाना चाहिए क्योंकि '71 बहुत पवित्र था, '71 बहुत अलग था। बांग्लादेश की आज़ादी के लिए बहुत ले लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। आप इसे 24वें विद्रोह के साथ कैसे जोड़ कर देख सकते हैं? लेकिन मैं ज़मात के ज्यादातर अखबारों में देखती हूँ और जब इसके नेता बोलते हैं, तब उनको सुनती भी हूँ, वे इसके लिए हमेशा दूसरी आज़ादी या दूसरी मुक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं।

मैं जमात- ए- इस्लामी में अपने एक परिचित से बात कर रही थी कि आप इस दूसरी आज़ादी या दूसरी मुक्ति से क्यों चिपके हुए हैं? क्या इसलिए कि पहली मुक्त में आपने 1971 में बेहद नकारात्मक भूमिका निभाई थी? तो क्या 1924 ने इसे जमात- ए- इस्लामी के लिए राजनीतिक रूप से बदल दिया, जिसने एक तरह से छात्र आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि वे वास्तव में आवामी लीग के छात्र संगठन, आवामी लीग के भीतर भी शरण लेते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आवामी लीग को नहीं पता था कि जमात के लोग आवामी लीग और उसके छात्र संगठन में शरण ले रहे हैं। मुझे लगता है कि आवामी लीग अति आत्मविश्वासी थी और उन्हें लगा कि शायद कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन फिर, जमात की यही विचारधारा थी, क्योंकि अगर वे आवामी लीग का हिस्सा नहीं बनते हैं, तो जो होता है वह यह कि वे यातना और गिरफ्तारी का निशाना बन जाते हैं। इसलिए, हाँ, इसके भीतर भी, यह एक समस्या बन जाती है।

अब इतिहास के पुनर्लेखन में, सिर्फ मुजीब का घर ही नहीं गिराया गया, 32 धानमंडी, बल्कि कई लोग यह भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यह फासीवाद का प्रतीक है, आवामी लीग ने मुजीब की विरासत को पूरी तरह से अपने अधिकार में ले लिया था। इसलिए मुजीब की विरासत बांग्लादेश की विरासत नहीं थी, यह पार्टी की विरासत थी। इसलिए अगर हमें नया बांग्लादेश चाहिए, तो मुजीब की विरासत, मुजीब से जुड़ी हर चीज खत्म होनी चाहिए। लेकिन साथ ही, 32 धानमंडी में पहले जो कुछ हुआ, उसे लेकर भी कई आलोचनाएं हो रही हैं।
5 अगस्त को 32 धानमंडी पर भी हमला हुआ। कुछ दिन पहले, मुझे लगता है कि आज या कल, लालोन उत्सव का विरोध हिफाज़त- ए- इस्लामी ने किया था, अब उसे रोक दिया गया है। इसलिए मैं बांग्लादेश में धार्मिक अधिकारों का दावा देख रही हूँ। सिर्फ जमात- ए- इस्लामी ही नहीं, बल्कि अन्य राजनीतिक दल, हिफाजत और अन्य भी हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है।

अब बांग्लादेश के राजनीतिक दलों पर बात कर लेते हैं, जैसा कि मैंने कहा, बीएनपी जल्द- से- जल्द चुनाव चाहती है क्योंकि वे सत्ता में आने के लिए प्रतीक्षारत पार्टी है। वो तैयार है। वास्तव में, मुझे लगता है कि 12 फरवरी से 25 फरवरी तक पूरे देश में बैठक करेगी। जमात- ए- इस्लामी सुधार चाहती है ताकि वे स्वयं को तैयार कर सकें। उनके पास चयन का प्रारंभिक दौर है, वे कह रहे हैं, प्रारंभिक तौर पर हमें अपने उम्मीदवारों की पहचान करनी है, लेकिन यह अंतिम नहीं है। अब सवाल यह है कि जहाँ तक आवामी लीग का सवाल है, कुछ लोग तर्क देते हैं कि अवामी लीग को जुलाई और अगस्त में जो कुछ भी किया उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। मुझे यह बहुत अजीब लगता है और मैं किसी से पूछता हूँ कि क्या जमात- ए- इस्लामी ने मुक्ति के दौरान हुई

हत्याओं के लिए माफ़ी मांगी है, लेकिन फिर भी वह चुनाव में भाग ले रही है और अब आप आवामी लीग की बात कर रहे हैं।

इसलिए मैं आवामी लीग की भागीदारी को नकारने के लिए एक संगठित प्रयास देख रहा हूँ। इसलिए यदि आवामी लीग भाग नहीं लेती है तो वास्तव में विपक्ष के लिए अन्य राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव लड़ने का अवसर उपलब्ध हो जाएगा, न कि बीएनपी द्वारा। जैसा कि मैंने कहा, बीएनपी निश्चित रूप से सत्ता में आएगी, जैसा कि प्रतीत होता है। मुझे विश्वस नहीं है कि छात्र एक नई राजनीतिक पार्टी कैसे बनाएंगे, लेकिन विपक्ष के लिए अवसर उपलब्ध है। किसी ने मुझे बताया, मैं अब अपनी प्रस्तुति समाप्त ही करने वाली हूँ, ग्रामीण इलाकों में जमात आवामी लीग को संरक्षण दे रही है। यह बात मुझे बांग्लादेश में पता चली। मैंने उनसे पूछा कि आवामी लीग जमात का समर्थन क्यों ले रही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जमात मजबूत है और चूंकि आवामी लीग बैकफुट पर है, इसलिए जमात उन्हें एक तरह से आश्रय दे रही है, जैसा कि अवामी लीग के छात्र संगठन ने पुलिस द्वारा पीछा किए जाने पर जमात इस्लामी को किया था। शायद यह बात है कि अगर अवामी लीग भाग नहीं लेती है, तो अवामी लीग के वोट का क्या होगा? क्या यह जमात- ए-इस्लामी को मिलेगा? यह एक प्रकार की गणना है जिस पर जमात काम कर रही है। लेकिन मुझे बहुत विश्वास नहीं है। अभी तक आवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने के बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ है। छात्र लीग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

आइए देखें कि छात्र राजनीतिक दल किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, नेता कौन है, एजेंडा क्या है और उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि अगर चुनाव इस साल के अंत में होता है, तो यह कैसे होगा। धन्यवाद।

वीणा सीकरी: स्मृति, वर्तमान स्थिति पर इतनी स्पष्ट प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। अब मैं डॉ. सोहिनी बोस से अनुरोध करती हूँ कि अपने विचार हमसे साझा करें। मुझे लगता है कि वे वर्चुअली हमसे जुड़ने वाली हैं, है ना? सुश्री सोहिनी बोस, क्या आप उपलब्ध हैं?

सोहिनी बोस: जी हाँ, नमस्कार, राजदूत जी।

वीणा सीकरी: अब आपकी बारी है।

सोहिनी बोस: आप सभी को मेरा नमस्कार। मुझे आप सब से जुड़ कर बहुत प्रसन्नता हो रही है...

वीणा सीकरी: क्या आवाज़ बढ़ाई जा सकती है? जी हाँ।

सोहिनी बोस: भारत- बांग्लादेश विदेश नीति पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए, जैसा कि यह वर्तमान में चल रही है, शुरू करने से पहले, मैं- आईसीडब्ल्यूए को मुझे आमंत्रित करने और अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के लिए अध्यक्ष महोदया को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मुझे जो कुछ कहना है उसमें से ज्यादातर बातें कही जा चुकी हैं लेकिन मैं विशेष रूप से विदेश नीति के बारे में बात करूँगी। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, भारत- बांग्लादेश संबंध दोनों सरकारों के बीच द्विपक्षीय संबंधों से परे और उससे भी अधिक गहरे हैं क्योंकि ये दोनों देश एक दूसरे के साथ अपना इतिहास साझा करते हैं, संस्कृति साझा करते हैं, वे भाषाएं, खान- पान की आदतें साझा करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण भौगोलिक कारक- जैसे भूमि, सीमा पार नदियाँ, 54 सीमापार नदियाँ और बंगाल की खाड़ी के पास का समुद्री क्षेत्र भी साझा करते हैं। इसलिए, यह एक भौगोलिक वास्तविकता है जिसे बदला नहीं जा सकता, चाहे दोनों देशों में से किसी भी देश में शासन का परिवर्तन हो या सरकार बदले।

लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस भौगोलिक वास्तविकता, इस संस्कृतिक बारीकियों का लाभ आपसी प्रगति और विकास के लिए उठाया जा सकता है, बशर्ते कि इन दोनों देशों के बीच शासन में पूरकताएं हों। अब, यह देखते हुए कि इस प्रकार की पूरकता भारत और बांग्लादेश के बीच अब तक की साझेदारी की पहचान थी, मुख्य रूप से भारत में वर्तमान मोदी सरकार और बांग्लादेश में शेख हसीना के नेतृत्व वाली पूर्वी आवामी लीग सरकार के साथ। लेकिन, इन साझेदारी को भारत- बांग्लादेश संबंधों में स्वर्णिम अध्याय क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि न केवल द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों का विस्तार हो रहा था, बल्कि दोनों देशों के बीच साझेदारी में विवाद के लंबित मुद्दों को पीछे छोड़कर द्विपक्षीय संबंधों को पोषित करने की क्षमता भी थी।

हालाँकि, अब बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के नेतृत्व में दोनों देशों के बीच इतने लंबे समय से चली आ रही यह साझेदारी रुक गई है। यह अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली एक नई सरकार है, और यह बांग्लादेश में अभी हो रही आर्थिक और राजनीतिक उथल- पुथल से निपटने की कोशिश कर रही है। इसलिए, वर्तमान में, भारत और बांग्लादेश दोनों ही बहुत ही अनजान क्षेत्रों का सामना कर रहे हैं और उन्हें यह तय करने के लिए समय की आवश्यकता होगी कि वे किस कूटनीतिक आधार पर अपने द्विपक्षीय संबंधों को फिर से शुरू करना चाहते हैं। लेकिन अब तक, अंतरिम सरकार की विदेश नीति के विकल्प उस अनिश्चितता का प्रक्षेपण हैं जिसका

सामना वह अपने घर में कर रही है और साथ ही अपनी स्वयं की वैधता से जूझ रही है जिसे इस बातचीत के हिस्से के रूप में पहले ही बताया जा चुका है।

अब, यह समझा जा सकता है कि संवैधानिक चेतावनी के कारण जो इस सरकार की वैधता पर सवाल उठाती है हालाँकि अब बांग्लादेश में उच्च न्यायालय द्वारा इसका समाधान कर दिया गया है, इस सरकार का लोकप्रिय समर्थन आधार बांग्लादेश में हुआ छात्र आंदोलन है। बहुत हद तक, छात्र आंदोलन में आवामी लीग विरोधी भावनाएं थीं, शुरू में नहीं, क्योंकि शुरू में यह कोटा आंदोलन था, लेकिन सरकार की कार्रवाई के साथ इसने बांग्लादेश में सरकार विरोधी रुख अपनाया। और इसका फायदा अन्य राजनीतिक ताकतों ने उठाया, जो बांग्लादेश में आवामी विरोधी बयानबाजी को हवा दे रहे थे, विशेष रूप से पिछले साल ढाका में चुनाव के बाद से। इसलिए, इसने आवामी विरोधी रंग ले लिया और विस्तार से, क्योंकि भारत- बांग्लादेश में हसीना शासन के साथ बहुत निकटता से जुड़ा हुआ है और इस सरकार की लगातार सत्ता में वापसी का समर्थन करता रहा, विस्तार से, इसने बांग्लादेश में जनता की भावनाओं के बीच भारत विरोधी भावना को भी उजागर किया, जो छात्र आंदोलन और उसके बाद की राजनीतिक कहानी की विशेषता थी, जो अगस्त क्रांति से ठीक पहले हुई थी। इसलिए, अब जब अंतरिम सरकार का गठन हो गया है, विशेष रूप से इस छात्र आंदोलन के लोकप्रिय समर्थन के आधार पर, यह अपने लिए एक ऐसी पहचान बनाने की कोशिश कर रही है जो आवामी लीग से बहुत अलग हो, यही वजह है कि हम आज इतिहास को फिर से लिखे जाने के बारे में बात कर रहे हैं, जो नई सरकार की घरेलू नीति का एक हिस्सा है।

अब चूंकि विदेश नीति भी घरेलू नीति का ही एक हिस्सा है इसलिए विदेश नीति में भी इसका असर देखने को मिलता है और आप देख सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश इस समय राजनीतिक दूरी बनाए हुए हैं क्योंकि भारत के साथ निकटता आवामी लीग सरकार की सबसे बड़ी आलोचनाओं में से एक रही है और अंतरिम सरकार एक ऐसी पहचान बनाने की कोशिश कर रही है जो इससे जितना संभव हो सके उतना अलग हो साथ ही क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री हसीना अभी भी भारत में शरण ली हुई हैं और प्रत्यर्पण के अनुरोध किए गए हैं लेकिन हमें अभी तक इसका जवाब नहीं पता है। इसलिए, यह आग में घी डालने का काम करता है और भारत- बांग्लादेश संबंध अब एक दूसरे से बहुत दूर हो गए हैं।

लेकिन, इन दोनों सरकारों की कूटनीतिक समझदारी यही है, भले ही भारत- बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में राजनीतिक साझेदारी की कमी है लेकिन दोनों सरकारों ने कूटनीतिक समझदारी और द्विपक्षीय परियोजनाओं को

शुरू किया है, उनमें से किसी को भी समाप्त नहीं किया गया है। उन्हों रोक दिया गया है और यही भारत-बांग्लादेश संबंधों की अभी की उम्मीद की किरण है। अब, अंतरिम सरकार की बात करें तो यह अपनी राजनीतिक साझेदारी में विविधता लाने की कोशिश कर रही है। एक बार फिर, आवामी लीग के साथ संबंधों को खत्म करते हुए, यह पाकिस्तान के साथ संबंधों को बेहतर करने की कोशिश में है जो बांग्लादेश में बढ़ते इस्लामीकरण के साथ- साथ चलता है।

अब, पाकिस्तान के साथ यह बढ़ती हुई साझेदारी बहुत बढ़िया है। यह बहुत अच्छी बात है कि बांग्लादेश अपनी राजनीतिक साझेदारी में विविधता लाने और उसे बेहतर करने का कोशिश कर रहा है और इसलिए व्यापार में वृद्धि हुई है, सुरक्षा बैठक हुई है, कुछ आर्थिक सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जिस स्थिति में है, वह भारत की जगह नहीं ले सकती। एक बार फिर, 1971 का अहसास कि हम भूगोल को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते। हमें समझना होगा कि भारत और बांग्लादेश बहुत बुनियादी रूप से एक- दूसरे पर निर्भर हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप व्यापार को देखें, तो तेल, साबुन, सब्जियाँ जैसी रोजमर्रा की जरूरतें, ये वो उत्पाद हैं जो सीमापार बांग्लादेश जाते हैं। बांग्लादेश से आने वाले मेडिकल पर्यटकों की संख्या सबसे ज्यादा है। साथ ही, अगर भारत अपने उत्तर- पूर्वी क्षेत्र का विकास करना चाहता है तो बांग्लादेश के सहयोग के बिना ऐसा कर पाना असंभव होगा।

इसलिए, पाकिस्तान के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाना बहुत अच्छी बात है लेकिन वे भारत की जगह नहीं ले सकते। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे बांग्लादेश सरकार को समझनवा होगा। दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश सरकार, अंतरिम सरकार को यह समझना होगा कि यह देश मुख्य रूप से विदेशी फंडिंग पर चलता है। भारत सबसे बड़े वित्त प्रदाताओं में से एक है। यह बांग्लादेश के लिए दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक गंतव्य है। भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। यह विदेशी सहायता के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। इसलिए, भारत की भूमिका को कम नहीं आंका जाना चाहिए। लेकिन, जब इस प्रकार की मदद रोक दी गई है और अमेरिका ने भी अपनी सहायता रोक दी है, तो बांग्लादेश को बहुत सावधान रहना चाहिए ताकि वह किसी खास देश के पक्ष में न बोले क्योंकि उसे अपनी राजनीतिक स्वायत्तता बचानी है। बांग्लादेश का भौगोलिक महत्व बहुत बड़ा है और इसलिए इसमें चीन, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई निवेशक हैं।

लेकिन अब, जब दो प्रमुख निवेशकों ने अपनी सहायता रोक दी है, तो बांग्लादेश को बहुत सावधान रहना होगा कि वह कूटनीतिक रूप से कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन एक बार फिर, परियोजना का निलंबन और समाप्ति नहीं, दोनों देशों के बीच संबंधों में आशा की किरण बनी हुई है और बेहतर भविष्य की उम्मीद जगाती है। धन्यवाद।

वीणा सीकरी: धन्यवाद। भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे पैनल के तीनों सदस्यों ने अलग- अलग पहलुओं को प्रस्तुत किया। यह बहुत दिलचस्प है। इसलिए मुझे लगता है कि दर्शकों के लिए हमारे पैनल के हर एक सदस्य द्वारा विश्लेषण किए गए तीन बहुत ही अलग-अलग पहलू हैं। अब हम संक्षिप्त प्रश्नोत्तर सत्र शुरू कर सकते हैं। जी, पहला सवाल।

अज्ञात वक्ताः नमस्कार, मैम। मेरा प्रश्न आपसे है। जैसा कि जुलाई के विद्रोह में महिलाओं की भागीदारी स्पष्ट रूप से देखी गई, आपको क्या लगता है- महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी शासन और प्रशासन में स्थानांतिरत हो गई है और बांग्लादेश के लिए बेहतर भविष्य की रूपरेखा बन चुकी है? पैनल के सदस्यों के लिए मेरा सवाल है कि क्या युवा सक्रियता के बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता का स्रोत बन जाने की संभावना है? या युवाओं की सक्रियता बांग्लादेश को इतिहास के उचित पक्ष पर बनाए रख सकती है? धन्यवाद।

वीणा सीकरी: जी हाँ। मैं एक साथ तीन सवाल लूंगी। जी हाँ, कृपया अपना प्रश्न पूछें।

अज्ञात वक्ता: अध्यक्ष महोदया धन्यवाद। मुझे लगता है कि यह बहुत ही अजीब है कि ट्रम्प बांग्लादेश के बारे में चुप्पी साधे हैं, जिस तरह से वे रूस और यूक्रेन, इज़रायल और गाज़ा में सक्रिए दिलचस्पी ले रहे हैं, और वे मैक्सिको, कनाडा, ग्रीनलैंड को पाने के लिए बहुत उत्सुक हैं। समस्या मार्शल में द्वीप के कारण शुरू हुई। इस प्रकार के भविष्य से निपटने के लिए अमेरिका का एजेंडा क्या है, क्या अमेरिका द्वीप पाने नें दिलचस्पी रखता है? या नहीं रखता?

वीणा सीकरी: हाँ, पीछे एक। हाँ। एक तीसरा सवाल।

आशीष: मेरा नाम आशीष है। मैं जेएनयू के सेंट्र फॉर साउथ एशियन स्टडीज़ केंद्र में पीएचडी प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। मेरा प्रश्नों प्रोफेसर भारद्वाज से है। महोदय, आपने बांग्लादेश में भारत की खुली छूट के बारे में अमेरिकी आशंकाओं के बारे में बात की। और कल ही राष्ट्रपति ट्रम्प ने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बात की थी अब उन्हें बांग्लादेश में जो कुछ भी करना है, वह करने की पूरी छूट है। तो क्या इससे बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों के बारे में अमेरिकी संदेह समाप्त हो गया है? दूसरा, जो कि इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है, कि अब जबकि भारत बांग्लादेश के साथ बातचीत कर सकता है, तो हमारे पास उस व्यापक उन्माद का मुकाबला करने के लिए क्या

नीतिगत विकल्प है जिसे जमात- ए- इस्लामी के नेतृत्व में बांग्लादेश में धार्मिक अधिकार पिछले जुलाई से फैला रहे हैं और अपवित्र अवामी लीग- भारत गठबंधन जो उन्होंने फैलाया है? धन्यवाद।

वीणा सीकरी: अच्छी बात है। हमारे पास सवाल आ चुके हैं। मुझे लगता है कि मुझे पैनल के हर एक सदस्य को इन सवालों का उत्तर देने के लिए आमंत्रित करना चाहिए और फिर आखिर में मैं भी इन सवालों पर अपनी राय दूँगी। क्या आप शुरुआत करना चाहेंगे? आप तीसरे सवाल का जवाब दे सकते हैं।

संजय भारद्वाज: मुझे लगता है कि मैं दूसरे और तीसरे, दोनों सवालों का जवाब दूँगा। अमेरिकी भागीदारी या अमेरिकी, आप कह सकते हैं, की दक्षिण एशिया में उपस्थिति,एक दशक या उससे अधिक समय में, यह समग्रता में देखा गया था। भारत ने पड़ोसियों को प्रबंधित किया और अपने पड़ोसी देशों को लोकतंत्र, मानवाधिकारों, अन्य विकासात्मक एजेंडों को बढ़ावा देने एवं ऐसे ही दूसरे कार्यों के लिए भारत के साथ मिल कर काम करने दिया। लेकिन बाइडेन प्रशासन, मेरे ख्याल से किसी तरह वे संबंधों के निजीकरण में फंस गए थे, जहां मोहम्मद यूनुस को संयुक्त राज्य अमेरिका में एक विशेष समर्थन प्राप्त है, और वे बांग्लादेश में सक्रिए रूप से शामिल हैं, दो साल या चार साल से नहीं, बल्कि अतीत में शेख हसीना शासन के खिलाफ इस प्रकार की शिकायतें रही हैं। मुझे लगता है कि उन्हें शेख हसीना की जगह मोहम्मद यूनुस को लॉन्च करने का अवसर मिला है लेकिन बहुत दिलचस्प बात यह है कि मोहम्मद यूनुस ही क्यों? क्योंकि मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में किसी भी राजनीतिक हितधारक ने स्वीकार नहीं किया था। जब मोहम्मद यूनुस... उनका नाम 2006 में सामने आया था, कि वे 2006 में कार्यवाहक सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में नेतृत्व कर सकते हैं, तब लगातार संकट थे और दोनों राजनीतिक दल एक साथ नहीं आ रहे थे। बीएनपी, जमात- ए- इस्लाम और आवामी लीग समेत सभी हितधारकों ने मोहम्मद यूनुस को अस्वीकार कर दिया है, नहीं, बांग्लादेश की राजनीति में उन्हें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया गया है। उन्हें सबसे अलोकप्रिय माना जाता था, विशेषरूप से कट्टरपंथी, वे मोहम्मद यूनुस को कभी पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनको माइक्रोक्रेडिट और ब्याज लेने की आदत थी। यह इस्लाम विरोधी है , जिसे आप व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता या शेख हसीना के खिलाफ और उस सब के बजाय देख सकते हैं।

लेकिन अब आप देख सकते हैं कि ये ताकतें, कट्टरपंथी और मोहम्मद यूनुस, वे एक साथ काम कर रहे हैं क्योंकि यह अमेरिकी थे, उन्हें अपने भू-रणनीतिक हितों को पूरा करने के लिए किसी के साथ काम करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। वे जमात- ए- इस्लाम के साथ काम कर रहे थे, वे कट्टरपंथियों के साथ काम कर रहे थे और वे मोहम्मद यूनुस को वहाँ लॉन्च करने में सहायक बन गए थे। इसलिए दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक

है व्यक्तिगत मुद्दे, व्यक्तिगत समीकरण और गणना। दूसरी थी, भू-रणनीतिक विचार। मुझे लगता है कि किसी तरह मुझे वह आशंका है जो अमेरिकियों को नहीं थी- उन्हें भारत पर भरोसा नहीं रहा कि भारत बंगाल की खाड़ी के मामलों का ध्यान रखेगा। जिस तरह चीन बांग्लादेश में, म्यांमार समेत दूसरे दक्षिण एशियाई देशों में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा था, बंदरगाहों का निर्माण कर रहा था। फिर मुझे लगता है कि अमेरिकी बहुत सक्रिए हो गए थे और वे अपनी उपस्थिति बनाना चाहते थे। मुझे यह भी लगता है कि भारत और हसीना दोनों को यह स्वीकार्य नहीं था। यह किसी भी तरह से शेख हसीना को सत्ता से बाहर करने में मददगार बन गया है।

दूसरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो आपने उठाया है, वह है- बांग्लादेशियों के बीच इस धारणा और नज़रिए को कैसे बदल सकते हैं कि उन्हें आज भी अधिकांश लोगों की तरह भारत विरोधी माना जाता है। मैं हाल ही में बांग्लादेश में था और मैं बीते 30 सालों से नियमित रूप से जाता रहा हूँ। इस बार, मेरे वहाँ के हर एक मित्र ने कहा, सावधान रहें और यह न कहें कि आप भारतीय हैं। मैंने सोचा, इतनी गहरी भारत विरोधी भावना क्यों है? मुझे लगता है कि पहली बात तो यह है कि किसी तरह से आवामी लीग या शेख हसीना विरोधी भावना इस भारत-विरोधी भावना से जुड़ गई है। यह एक कारण है कि जो कोई भी आवामी लीग का विरोधी है, जो उसका समर्थक है, वह हमारे लिए अच्छा नहीं है। अब, लोकप्रिय आख्यान और भावनाएं शेख हसीना के खिलाफ थीं। मुझे नहीं पता, आज अगर चुनाव होते हैं, तो मैं शर्तिया कह सकता हूँ कि आज भी 30% वोट शेख हसीना या आवामी लीग को ही मिलेंगे।

मुझे लगता है कि ये बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं और हमें इनसे निपटना है। हम निष्पक्ष रूप से काम कर रहे हैं। हमने सबसे बड़ा निवेश किया है, ऐसा देश जिसे सबसे बड़ी लाइन ऑफ क्रेडिट दी है, वह बांग्लादेश ही है। हमने उनके विकास परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बांग्लादेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जैसे कई क्षेत्र हैं। वे हमेशा घाटे में चल रहे थे, लेकिन भारत की मदद से अब बांग्लादेश के लिए मुनाफा कमा रहे हैं। हमने रेलवे और हर एक चीज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए भारत ने लोगों के नज़रिए को बदलने के लिए कड़ी मेहनत की लेकिन भावनाएं और स्थितियां बदल गईं। एक चीज जो भारत, मुझे लगता है कि अभी भी कर सकता है, वह है, हमें बांग्लादेश में लोकतांत्रिक शक्तियों को हमेशा बढ़ावा देना चाहिए। वे लोकतांत्रिक शक्तियाँ कुछ भी हो सकती हैं।

मुझे लगता है कि हमें इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए कि यह युक्ति ज्यादा उपयुक्त होगी या वह युक्ति। मुझे लगता है कि हमें बांग्लादेश में लोकतांत्रिक मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहिए। विशेष रूप

से, मैं बांग्लादेश के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि बांग्लादेश इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है कि एक बार जब वहाँ लोकतांत्रिक मूल्य और साख बन जाएगी तो ज्यादातर लोग, या मैं कह सकता हूँ कि कुछ लोगों को छोड़कर, जमात- ए- इस्लाम और पाकिस्तान समर्थक, और '47, ज्यादातर लोग बांग्लादेश में लोकतांत्रिक संस्थाओं एवं लोकतंत्रीकरण को पसंद करते हैं। यह अपने आप ही इस नज़रिए को बदल देगा कि भारत बांग्लादेश में लोकतांत्रिक ताकतों का समर्थन कर रहा है।

स्मृति पटनायक: देखिए, युवा सक्रियता के मुद्दे पर, मुझे लगता है कि क्या यह अस्थिरता का स्रोत हो सकता है। यही पूछा गया था। मुझे लगता है कि युवा सक्रियता हमेशा से बहुत- बहुत आकांक्षापूर्ण रही है और अगर आप बांग्लादेश के संदर्भ में देखें, तो इसकी शुरुआत कोटा सुधार आंदोलन से हुई। जाहिर है, जिस प्रकार से शेख हसीना की सरकार ने उस समय कोटा सुधार आंदोलन से निपटा, उसने वास्तव में आवामी लीग विरोधी ताकतों को इसका फायदा उठाने का मौका दिया। बांग्लादेश में मंहगाई और चुनाव के तरीकों को लेकर पहले से ही जमीन पर बहुत असंतोष था। इसलिए यह एक बड़े पैमाने पर राजनीतिक आंदोलन में बदल गया।

बहुत कम समय लेते हुए, भारत- आवामी लीग के मुद्दे पर, यह एक ऐसा सवाल है जो हमेशा उठता है। बांग्लादेश में, कई लोग पूछते रहते हैं, भारत ने अपना सबकुछ दांव पर लगा दिया। मेरा सवाल हमेशा से यही रहा है कि क्या भारत के पास कोई दूसरा विकल्प उपलब्ध था या नहीं। मुझे लगता है कि भारत की स्थिति बांग्लादेश या कहीं से भी सत्ता में रहने वाली किसी भी राजनीतिक पार्टी से निपटने की रही है। हमने अतीत में पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के संदर्भ में सैन्य शासन से निपटा है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई प्रतिबंध है, कि हम किसी विशेष राजनीतिक शक्ति का मुकाबला नहीं करेंगे।

दूसरा यह है कि 2014 नहीं, माफ करें, तीन चुनाव - 2014, 2018, और 2024 के चुनाव, पूरे दो चुनाव, आवामी लीग द्वारा आंतरिक शक्तियों का इस्तेमाल करके पूरी तरह से उनका खाका तैयार किया गया था। पुलिस उनके साथ थी। सेना उनके साथ थी। इसलिए उन्होंने योजना बनाई। इसलिए अगर देश में इसका विरोध करने और भारत पर आरोप लगाने के लिए कोई आंदोलन नहीं दिखता तो मुझे नहीं लगता कि भारत किसी भी प्रकार के लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। हम लोकतंत्र को प्राथमिकता देते हैं लेकिन हम सक्रिए रूप से शामिल होकर और किसी तरह का चुनाव करवाकर लोकतंत्र को बढ़ावा नहीं देंगे। संक्षेप में, जब भी भारत ने, वास्तव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से संपर्क करने की कोशिश की है, तो उसने हमेशा, नेशनलिस्ट पार्टी भी भारत के साथ दिखने के बारे में बहुत सावधान रहती है, क्योंकि इसका वोट आधार भारत विरोधी निर्वाचन क्षेत्र है। वास्तव में, यदि

आप खालिदा जिया द्वारा 2012 में दिए गए साक्षात्कार को देखें, जब वह भारत आई थीं, उस समय, कई लोगों ने पूछा था कि यदि आप भारत के साथ अच्छे संबंधों के बारे में पूछ रही हैं तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र का क्या होगा? उनका जवाब था कि आप पीछे का शीशा देखकर गाड़ी नहीं चला सकते। आपको सामने की तरफ देखना होगा। लेकिन सवाल यह है कि बीएनपी का निर्वाचन क्षेत्र बहुत अलग है, इसलिए वे हर प्रकार की आवाज़ उठाएंगे। सार्वजनिक रूप से, वे भारत के साथ अच्छे संबंधों को स्वीकार नहीं करना चाहेंगे। साल 2001 से 2006, शायद, भारत में संबंधों का सबसे बुरा दौर था।

मैं '75 के बारे में भी नहीं कहूँगीं जब सैन्य शासन था। मुझे नहीं लगता कि हमने उस प्रकार से कष्ट झेले हैं जैसा कि 2001 से 2006 के बीच झेला था। देश भर में बम विस्फोट हुए। चटगांव जेटी में 10 ट्रक भर कर हथियार उतारे गए। फिर इन सब बातों के बाद, अगर कोई यह कहता है कि आपके आवामी लीग के साथ अच्छे संबंध क्यों हैं, बीएनपी के साथ क्यों नहीं, तो बीएनपी को बहुत स्पष्ट रूप से यह बताना होगा कि वास्तव में भारत के साथ किस प्रकार के संबंध रखने की जरूरत है। धन्यवाद।

वीणा सीकरी: जी हाँ, धन्यवाद। सुश्री बोस, क्या आप कुछ कहना चाहेंगीं? सुश्री सोहिनी बोस, क्या आप ऑनलाइन हैं? हम आपको सुन नहीं पा रहे। कृपया स्वयं को अनम्यूट करें। हमें आवाज़ नहीं आ रही। कोई आवाज नहीं है। बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही। क्या आप फिर से कनेक्ट कर सकते हैं, कृपया फिर से कनेक्ट करें। इस बीच, जी हाँ, आप कुछ पूछना चाहती हैं। जी पूछिए।

मधुरिमा प्रमाणिक: मैं मधुरिमा प्रमाणिक हूँ। मैं जामिया की एक शोध छात्रा हूँ। मैं जानना चाहती हूँ... नमस्ते, मैं मधुरिमा प्रमाणिक हूँ, जामिया मिलिया इस्लामिया की शोध छात्रा। मेरा सवाल है- आवामी लीग के पतन के बाद हिंदुओं पर शोषण का मुद्दा उठता है। बौद्ध इसाई एकता परिषद के अनुसार लगभग 700 से 800 हिंदुओं ने भागने की कोशिश की, भारत में शरण लेने के लिए। इस मामले में भारत का क्या रुख है? हमें सीमा सुरक्षा पर कैसे ध्यान देना चाहिए? एक पड़ोसी देश होने के नाते हमें अभी बांग्लादेश को किस तरह से देखना चाहिए?

वीणा सीकरी: बहुत अच्छी बात है, जी हाँ कोई दूसरा सवाल? मुझे लगता है कि अब कोई और सवाल नहीं है। मैं एक बार फिर से जवाब देने का मौका देती हूँ। मैं सिर्फ एक सवाल का जवाब देना चाहती थी, पहला सवाल जो मुझसे पूछा गया था, महिलाओं की भागीदारी पर। मुझे लगता है कि यहाँ यह जानना चाहिए कि, हाँ, कोटा

सुधार आंदोलन में बहुत सी महिलाएं थीं। लेकिन मुझे लगता है कि 15 जुलाई के बाद, जब हिंसा शुरु हुई, और वास्तव में सब कुछ इस्लामी छात्र शिविर द्वारा नियंत्रित कर लिया गया, जमात- ए- इस्लामी की युवा शाखा, सड़कों पर महिलाओं की संख्या बहुत कम पाई गई। इसलिए मुझे लगता है, वास्तव में, महिलाओं की भागीदारी के बारे में मिथक वास्तव में कोटा सुधार आंदोलन था। जब इस्लामी छात्र शिविर ने इसे नियंत्रित किया, तो वे लोग चले गए। 21 जुलाई को, जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि हाँ, हम आरक्षण को घटाकर केवल 5% करने जा रहे हैं, उस समय आरक्षण सुधार आंदोलन में शामिल इन महिलाओं ने स्वयं कहा कि हाँ, हम किसी भी प्रकार के आंदोलन में अपनी भागीदारी वापस लेने जा रहे हैं। हम सरकार के साथ अलग से बातचीत करने जा रहे हैं। हमारी नौ सूत्री मांगें हैं, और उन्होंने वे मांगे सरकार के सामने रखीं।

मुझे लगता है कि केवल 15, 20 दिनों में, 15 या 16 जुलाई से 5 अगस्त तक यह आंदोलन एक हिंसक आंदोलन में बदल गया था। इस आंदोलन ने ही असल में सरकार को गिराया। मुझे लगता है कि बाकी दुनिया को जो सिद्धांत दिया गया था, कि यह छात्रों का स्वतःस्फूर्त विद्रोह है, मेरे विचार से उस मिथक को मोहम्मद यूनुस ने खुद ही तोड़ दिया जब उन्होंने सितंबर 2024 में न्यूयॉर्क के क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव में बात की। उन्होंने खुद कहा कि, ऐसा मत सोचो कि यह अपने आप हुआ। इसे बहुत सोच- समझकर किया गया था। उन्होंने अपने स्वयं के विशेष सहायक, महफूज़ आलम को पेश किया जो बाद में सलाहकार बन गए। उन्होंने इस महफूज आलम को पूरी योजना के पीछे मास्टरमाइंड के रूप में पेश किया। जाहिर है, यह तथ्य कि जमात- ए- इस्लामी और पाकिस्तान की अन्य ताकतों और सेना के इस्लामी खंड के माध्यम से लंबे समय से इसती योजना बनाई गई थी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें महिलाओं की कोई भूमिका थी।

मुझे लगता है कि आपने हिंदुओं, बौद्धों और ईसाइयों एवं उन पर हुए हमलों के बारे में जो कहा, इसके बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार, सच में उनके देश छोड़ कर भागने के लिए कोई व्यापक आंदोलन नहीं हुआ है। हालाँकि यह उन हमलों से बहुत स्पष्ट है जो हो रहे हैं, संपत्ति का विनाश, प्रतिष्ठानों पर कब्ज़ा करना और इसी तरह की घटनाएं और कई हिंदुओं, बौद्धों और ईसाइयों से, सरकारी नौकरियों से या विश्वविद्यालयों या स्कूलों में जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया। फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम बांग्लादेश के नागरिक हैं। हम यहाँ रहना चाहते हैं और हमें हमारे हक चाहिए। वास्तव में, उन्होंने मोहम्मद यूनुस सरकार से आठ सूत्री मांग की, लेकिन मोहम्मद यूनुस ने उनकी मांगों को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ कर दिया। फिर भी, सीमा पर उनकी तरफ से कोई दबाव नहीं है। सीमा बंद है लेकिन आपको उनकी तरफ से कोई दबाव नहीं दिखता।

वे तो बांग्लादेश में ही रहना चाहते हैं और अपनी स्थिति को मजबूत बनाना चाहते हैं। आप कुछ और कहना चाहेंगे?

संजय भारद्वाज: बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों के बारे में, यदि आप करीब से देखें, तो बहुत सारे अध्ययन किए गए हैं। जैसे- बरकतुल्लाह ने भी एक अध्ययन किया है। आपके देखा है और यदि आप आँकड़ों पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि बांग्लादेश में हिंदुओं को विकास संबंधी समस्याएं नहीं हैं। वे अच्छे कारोबारी हैं। वे हर क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं। लेकिन राजनीतिक भेदभाव की समस्या है और सुरक्षा संबंधी खतरे भी हैं। हम नियमित रूप से पढ़ रहे हैं कि उनके मंदिरों और पूजा पंडालों पर हमला किया गया है, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को कई बार पीटा गया है, मार डाला जाता है, ऐसी कई घटनाएं हमने देखी हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि, मैडम ने इसके संकेत भी दिए हैं- सेना, प्रशासन, शैक्षणिक संस्थानों, कुलपतियों, आप कहीं भी हिन्दुओं को नहीं पाते, आवामी लीग के सत्ता में होने के बावजूद। बांग्लादेश में हिन्दू समुदाय के लोगों को बहुत कम अवसर दिए गए हैं। बांग्लादेश की राजनीति में बहुसंख्यकवादी विमर्श हावी है और इसी कारण हिंदू पलायन करने, विदेश जाने को मजबूर हैं, वे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

जातीय संसद में भी, अगर आप अल्पसंख्यकों को देखेंगे तो महिलाओं समेत 350 सीटें हैं, आप पाएंगे कि 12 सदस्य अल्पसंख्यक समुदायों से हैं। तो ये... समावेशिता, बंगाली सांस्कृतिक समाज और इस प्रकार के वे नारे दे रहे हैं लेकिन समस्या यह है कि आबादी के लिहाज से हिंदुओं को वर्षों से व्यवस्थित रूप से हाशिए पर रखा गया है। आप देख सकते हैं कि आज उनकी आबादी आठ प्रतिशत से भी कम है और मुझे लगता है कि इसीलिए मैं इस बात पर ज़ोर दे रहा था कि किसी देश की लोकतांत्रिक साख को छीना नहीं जाना चाहिए, उसे कम नहीं किया जाना चाहिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए उन्होंने 1971 में अपने जीवन का बलिदान दिया, 30 लाख लोग लोकतंत्र के लिए मारे गए, वह कहाँ है? लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ सभी राजनीतिक दलों के एक हिस्से ने समझौता किया है... बीएनपी और जमात गठबंधन और उनके काम करने के तरीके को भूल जाइए, कट्टरपंथी ताकतों के साथ सांठ- गांठ करके बांग्लादेश को अगला अफगानिस्तान बना दीजिए। लेकिन अन्य राजनीतिक ताकतें भी इसके साथ इंसाफ नहीं कर रही हैं, वे अल्पसंख्यक समुदायों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल भर कर रही हैं। मुझे लगता है कि हमें तर्कसंगत होने की जरूरत है, हमें यह सोचने की जरूरत है कि बांग्लादेश में हम जिस भी राजनीतिक हितधारकों का समर्थन कर रहे हैं, वे नीतियाँ बनाते समय और भागीदारी करते समय समावेशिता का कितना ध्यान रख रहे हैं, और बांग्लादेश में निर्णय लेने एवं नीति बनाने की प्रक्रिया में वे कितनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। यह बहुत चिंताजनक है, बहुत महत्वपूर्ण है। जब डोनाल्ड ट्रम्प इस बारे में बात कर रहे हैं

कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय मारे जा रहे हैं और उन पर अत्याचार हो रहे हैं तो क्या बचा रह गया है? दुनिया जानती है और सिर्फ दूसरे अल्पसंख्यक, हर कोई नारे दे रहा है, लेकिन हिन्दू जा रहे हैं, फिर को नहीं, हम चुप हैं। मुझे लगता है कि इस मामले को बहुत सावधानी और दृढ़ता के साथ निपटाए जाने की जरूरत है अन्यथा भारत ही स्वाभाविक गंतव्य होगा। पाकिस्तान में कोई हिंदू नहीं बचा है, अफगानिस्तान में कोई हिंदू नहीं बचा है, और कल आपको बांग्लादेश में भी एक भी हिंदू नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे लगता है कि इसके लिए बहुत ठोस नजरिया अपनाने की जरूरत है। धन्यवाद।

स्मृति पटनायक: मुझे लगता है कि हसीना के पतन के बाद बहुत जल्दी ही देश में पूरी तरह अराजकता फैल गई। पुलिस ने अपनी चौकियां छोड़ दीं क्योंकि सभी चुनावों में पुलिस की मिलीभगत देखी गई। वे शासन द्वारा दी जाने वाली यातना का हिस्सा थे। इसलिए इस पूरी अराजकता में, हिंदुओं और आवामी लीग समर्थकों पर हमला देखा गया। अंतरिम शासन का कहना है कि ये हमले केवल इसलिए नहीं हुए क्योंकि हिंदू धार्मिक अल्पसंख्यक थे बल्कि वे आवामी लीग के समर्थक थे। लेकिन ऐसा कहने के बाद, मुझे लगता है कि ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ एक खास समुदाय के खास लोगों ने वास्तव में मौके का फायदा उठाया। हिंदुओं पर भी हमला किया गया। दरअसल, साथ ही, जब आप इन अल्पसंख्यक हमलों को देखते हैं, तो आप पाते हैं कि कुलपति समेत अधिकांश प्रमुख हिंदू अधिकारी, जो निर्णायक पदों पर थे, उन्हें मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा। मुझे इसकी जानकारी है कि कुछ विश्वविद्यालय के कुलपतियों को इस्तीफा देना पड़ा है। पुलिस अधिकारियों और दूसरे लोगों को सच में, हसीना के बाद मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ा है।

लेकिन वर्तमान में, जैसा कि महोदया ने भी बताया, मुझे लगता है कि हिंदुओं का बांग्लादेश में बने रहना अच्छा होगा। उन्हें अपनी जंग लड़ने दें। वे चुनाव आयोग में पंजीकृत हिंदू राजनीतिक पार्टी बनाने की योजना तैयार कर रहे हैं। यह पहली बार है जब उनके पास एक हिंदू राजनीतिक पार्टी होगी। इससे पहले, उनका वोट ज्यादातर आवामी लीग और बीएनपी के बीच बंटता था। बीएनपी में भी हिंदू नेताओं की अच्छी- खासी संख्या है। इसलिए वे भी एक आरक्षित सीट की मांग कर रहे हैं, अलग से निर्वाचक मंडल नहीं बल्कि संसद में आरक्षित सीट। लेकिन मुझे नहीं लगता कि संवैधानिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में ऐसा कुछ आया है। मैंने हिंदुओं के लिए कोई आरक्षित सीट बनते नहीं देखा।

इसलिए मुझे लगता है कि बांग्लादेश में कोई भी व्यक्ति, अगर वह उदारवादी, धर्मनिरपेक्ष है, तो वह हमेशा चाहता है कि हिंदू बांग्लादेश में ही रहें। इसलिए यह जंग बहुत बड़ी है, सिर्फ मुस्लिम उदारवादियों तक ही सीमित

नहीं है। यह एक उदारवादी शक्ति होगी। इसलिए वे एक- दूसरे की ओर देखते हैं। बांग्लादेश में समर्थन के लिए हिंदू, मुस्लिम उदारवादी तत्वों की ओर देखते हैं। मुस्लिम उदारवादी तत्व भी हिंदुओं की ओर देखते हैं। इस तरह वे सोचते हैं कि अगर बड़ा इस्लामीकरण हुआ तो वे टिक सकते हैं। आपके पास एक शक्ति भी है जो बडे इस्लामीकरण के खिलाफ लड़ सकती है।

वीणा सीकरी: ठीक है। क्या सुश्री बोस अब हमसे जुड़ चुकी हैं? आप उनको उत्तर देने के लिए कह सकते हैं।

सोहिनी बोस: क्या अब आप मुझे सुन पा रही हैं?

वीणा सीकरी: जी हाँ, कृपया अपनी बातें जारी रखिए।

सोहिनी बोस: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत कम समय लूंगी। जहाँ तक भारत- आवामी लीग सांठ-गांठ की बात है, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से, लोगों की भावनाओं को न समझने का कहकर, या एक राजनीतिक दल के साथ काम करने का आरोप लगाते हुए भारत की बार- बार आलोचना की गई है। बांग्लादेश के साथ उसका पार्टी आधारित कारोबारी रिश्ता है। मैं यहाँ यह बताना चाहूँगी कि भारत केवल उसी सरकार के साथ काम करता है जो उसके साथ अच्छे तरीके से काम करती है। और अगर आप मोदी सरकार और आवामी लीग सरकार द्वारा बीते जून या जुलाई में जारी किए गए अंतिम संयुक्त वक्तव्य को देखें, तो उन्होंने कहा था कि वे एक- दूसरे के साझा हितों के प्रति संवेदनशील हैं। साझा हितों के प्रति यह संवेदनशीलता एक ऐसी चीज़ है जो क्षेत्रीय परिदृश्य में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब हम देखते हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ अपनी राजनीतिक साझेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, चीन के साथ अपनी साझेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बेशक, चीन के साथ बांग्लादेश ने पहले से ही संबंध बनाए रखे हैं लेकिन संतुलन की कूटनीति थी जो किसी भी देश के साथ बांग्लादेश के जुड़ाव में महत्वपूर्ण थी। मुझे लगता है कि अगर बांग्लादेश को संतुलन की उस कूटनीति को बनाए रखने की जरूरत है, भले ही वह आने वाले वर्षों में अपनी खुद की राजनीतिक स्वायत्त आवाज़ को बनाए रकना चाहता हो। इसलिए यह पारस्परिक संवेदनशीलता महत्वपूर्ण है। यह तभी संभव है जब यह पारस्परिक हो, तभी भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध मजबूत हो सकेंगे।

साथ ही, मुझे लगता है कि मीडिया और सोशल मीडिया इस समय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, विशेषरूप से तब जब दोनों देशों के बीच लोगों की भावनाएं एक- दूसरे से अलग हो रही हैं। यही समय है जब लोग सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके फिर से जुड़ सकते हैं और दोनों देशों के बीच मौजूद

समानताओं और मूल्यों को संजो सकते हैं। बेशक, राजनीतिक कहानी बहुत अलग है। लेकिन यह समझने के लिए किए लोग वास्तव में क्या चाहते हैं, मुझे लगता है कि लोगों को खुद के लिए बोलते हुए सुनना बहुत महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि हर समय राजनीतिक राग आलापा जाए। धन्यवाद।

वीणा सीकरी: धन्यवाद। मुझे लगता है कि यह सभी सवालों का अच्छा सार था। मुद्दे पर आपके दिलचस्पी दिखाने का धन्यवाद। मैं आखिर में कुछ शब्द कहना चाहूँगी और फिर हम सब चाय ब्रेक लेंगे। मुझे लगता है कि हमने बांग्लादेश की स्थिति पर अच्छी चर्चा की है। यह बात हर बीतते दिन के साथ बिल्कुल स्पष्ट होती जा रही है कि सत्ता परिवर्तन अभियान के तहत सत्ता पर कब्जा किया जा रहा है। सत्ता पर कब्ज़ा मुक्ति- विरोधी युद्ध बलों द्वारा किया जा रहा है, 1971 के वे लोग जो 1971 के मुक्ति संग्राम के खिलाफ थे, वही लोग जो बांग्लादेश के संविधान के उन चार सिद्धांतों के लिए खड़े नहीं हैं जिनका आपने उल्लेख किया है, वे लोग जो धार्मिक ताकतों, धार्मिक चरमपंथ की ताकतों के लिए खड़े हैं, वे ही हैं जिन्होंने बांग्लादेश में सत्ता पर कब्ज़ा करने की कोशिश की है। अंतरिम सरकार शासन, आप इसे जो भी कहें, यहाँ तक कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस भी, वे केवल अपने इशारे पर काम कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। यह एक महत्वपूर्ण बात है लेकिन हमने इसे बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की सभी मूर्तियों के विनाश से देखा है और आपने सभी चीजों का नाम बदलकर देखा, वे संविधान को बदलना चाहते हैं, वे राष्ट्रीय ध्वज को बदलना चाहते हैं, वे राष्ट्रगान को बदलना चाहते हैं।

लेकिन सवाल यह है कि बांग्लादेश के लोगों की ओर से इस पर कड़ा विरोध हुआ है, क्योंकि वे नहीं चाहते कि 1971 के मुक्ति संग्राम की यादें मिट जाएं। ऐसे कई लोग हैं जो वास्तव में मुक्ति संग्राम का हिस्सा थे, वे 1971 में किशोरावस्था में थे, और अब वे शायद 60 और 70 के दशक वाले साल के हैं लेकिन उन्होंने इन मूल्यों को अगली पीढ़ी तक पहुँचाया है, स्कूल की किताबों, कॉलेज की किताबों में। खास तौर पर शेख हसीना के शासन में, 15 वर्षों में, मुक्ति संग्राम के बारे, एक देश के रूप में बांग्लादेश का क्या मतलब है, के बारे में बड़ी- बड़ी प्रस्तुतियां दी गई हैं और इस पर निश्चित रूप से विरोध हुआ है। इस पर पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए शासन ने अपने बयानों को संयमित करने की कोशिश की है और नहीं, नहीं, हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं फिर भी, वे सुधार कार्यों के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

स्थिति का दूसरा पहलू यह है कि यह बहुत ही भयंकर आवामी लीग विरोधी है और मुझे लगता है कि इसके साथ ही, निश्चित रूप से, भारतीय विरोधी भावना जुड़ी हुई है लेकिन मूल रूप से यह अवामी लीग विरोधी एक बहुत ही मजबूत स्थिति है जहां वे उन्हें फासीवादी कर रहे हैं और वे उन्हें राजनीतिक ढांचे से पूरी तरह से बाहर

करना चाहते हैं। छात्र लीग और अब आवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास लेकिन फिर से, यह वास्तव में बांग्लादेश के लोगों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि मुझे लगता है कि 30-40% वोट बैंक पूरी तरह से बरकरार है, जैसा कि हमारे पैनल के सदस्यों ने भी बताया है। इसलिए, हमने देखा है कि आवामी लीग को बाहर करने का यह प्रयास स्वीकार्य नहीं हो रहा है। यहां तक कि खुद बीएनपी भी आवामी लीग के चुनाव में भाग लेने के पक्ष में सामने आई है क्योंकि उन्हें लगता है कि पंजीकृत राजनीतिक दल पर प्रतिबंध लगाने का यह काम लोकतांत्रिक नहीं है। इसलिए मूल रूप से मुझे लगता है कि बांग्लादेश के लोगों का हित लोकतांत्रिक संरचना की ओर वापसी कर रहा है और बांग्लादेश के लोगों को निर्णय लेने देन चाहिए, जल्द- से- जल्द स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव होने चाहिए।

कोई भी इंतज़ार नहीं करना चाहता, साल का अंत भी थोड़ा लंबा था क्योंकि बीएनपी ने पहले ही अगस्त की बात कह दी थी। इसलिए मुझे लगता है कि यही बात है और बिना किसी सुधार के मौजूदा संविधान के तहत चुनाव कराना क्योंकि सुधार शासन- कक्ष संचालन का जनादेश नहीं है। मेरे ख्याल से, मैं यहाँ भारत- बांग्लादेश संबंधों के बारे में उल्लेख करना चाहूँगी जिसके बारे में सुश्री सोहिनी बोस ने बहुत विस्तार से बात की। मुझे लगता है कि भारत सरकार ने पहले दिन से ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी कि हम वर्तमान सरकार से निपटने के लिए तैयार हैं।

और हाँ, अंतरिम शासन से कोई वापसी नहीं हुई। वास्तव में उनमें से किसी ने भी भारत आने या भारत से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वे मीडिया कूटनीति, मेगाफोन कूटनीति, मीडिया से बात करते रहे, बयान देते रहे कि- अरे हम ये बदलना चाहते हैं, अरे हम वो बदलना चाहते हैं। यह ठीक नहीं है, यह अच्छा नहीं है। यह हमारे हितों के अनुरूप नहीं है। लेकिन मेरे कहने का अर्थ है, यदि आप यह सब करना चाहते हैं तो आपको किसी से बात करनी होगी, है न? आप इतना शोर मचा कर इस आसरे में शांत नहीं बैठ सकते कि कुछ तो हो ही जाएगा।

भारत ने पहल की और हमारे विदेश सचिव ने 9 दिसंबर को बांग्लादेश का दौरा किया। मुझे लगता है कि यह एक सफल दौरा था लेकिन बांग्लादेश की तत्कालीन सरकार की ओर से इस पर कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने वास्तव में अभी तक कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। शायद इस सप्ताहांत ही कुछ सलाहकार के बीच मस्कट या ओमान में बैठक हो सकती है। फिर भी, मेरे विचार से अल्पसंख्यकों के साथ किए गए व्यवहार ने भारत में बांग्लादेश के खिलाफ बहुत ज्यादा भावनाएं जगाई हैं। इसके खिलाफ लोगों में बहुत गुस्सा है। कई

राज्यों में, सिर्फ पश्चिम बंगाल या त्रिपुरा में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में प्रदर्शन हुए हैं। वास्तव में, और फिर से, बांग्लादेश में भी प्रतिक्रिया का कारण बना है। भारत में मीडिया अतिशयोक्ति कर रहा है और इसी तरह की बातें कर रहा है। इससे और भी ज्यादा दुश्मनी पैदा हुई है क्योंकि यह मीडिया की अतिशयोक्ति नहीं है, यह असल में लोग ही हैं। हमने देखा है कि लोगों ने अपने परिवार खो दिए, घर का कमाने वाला खो दिया और दो देशों के बीच बहुत ज्यादा नफरत पैदा कर दी है। अब हमें देखना होगा कि क्या शासन इस दिशा में आगे बढ़ने में दिलचस्पी रखता है।

मुझे लगता है कि हमने कल ही देखा है, मुझे यह नहीं पता कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट का यह अंक देखा है। उन्होंने बांग्लादेश की सरकार, मोहम्मद यूनुस की सरकार द्वारा बांग्लादेश आने और रिपोर्ट लिखने के लिए आमंत्रित किया गया था लेकिन केवल बहुत ही कम समय अवधि पर, 15 जुलाई से 5 अगस्त के बीच की अवधि पर। फिर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, पहले वोल्कर तुर्क दौरे पर गए फिर मानवाधिकार आयोग ने दो प्रतिनिधिमंडल भेजे, लेकिन वे चले गए, उन्हें पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई। मुझे लगता है कि कल ही रिपोर्ट आई है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जबकि यह रिपोर्ट कुछ घटनाओं के बारे में बात करती है, यह अल्पसंख्यकों के खिलाफ कुछ घटनाओं, 5 अगस्त के बाद हुई हत्याओं के बारे में भी बात करती है। इसके बेहद रोचक निष्कर्ष में यह भी कहा गया है कि हमारे पास किसी भी व्यक्ति के अपराध को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं है और हमें लगता है कि अभी और जांच किए जाने की जरूरत है। उन्हें अधिक व्यापक आधार वाली जांच की आवश्यकता है, न केवल यह देखते हुए कि 15 जुलाई से 5 अगस्त के बीच क्या हुआ बल्कि यह भी कि 5 अगस्त के बाद क्या हुआ क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग जानते हैं कि इस वर्तमान शासन ने 5 अगस्त के बाद हुई किसी भी घटना के लिए स्वयं की क्षतिपूर्ति की है। इसलिए अगर उनके द्वारा कोई हत्या की गई है तो उसकी भरपाई की गई है जबकि हम जानते हैं कि कुछ, यहां तक कि सलाहकार, सखावत हुसैन, उन्होंने खुद कहा कि- थानों की लूट हुई थी और इसकी जांच होनी चाहिए और जब उन्होंने पुलिस स्टेशनों को लूटा, उन्होंने हथियार चुरा लिए, उन्होंने पुलिसकर्मियों को मार डाला, इसकी जांच होनी चाहिए। तो बांग्लादेश में वर्तमान शासन के सलाकार ने यह सब कहा, लेकिन उसे नौकरी से हटा दिया गया, इसलिए वह अब नहीं है, उसकी आवाज अब नहीं है। जाहिर है, इसका मतलब है कि आप अगर कोई जांच करने जा रहे हैं तो यह बहुत व्यापक आधार वाली जांच होनी चाहिए, जिसमें कोटा सुधार आंदोलन, छात्रों, भेदभाव विरोधी आंदोलन, जो वे अब खुद को कहते हैं और अल्पसंख्यकों की हत्या, जिस तरह से बांग्लादेश में लोकतंत्र को आगे नहीं बढ़ने दिया गया, यह सब शामिल है। निश्चित रूप से इसकी अधिक विस्तृत जांच की आवश्यकता है।

आखिर में, हमारे पास निश्चित रूप से वैश्विक दर्जा है और राष्ट्रपति ट्रम्प ने कल जो कहा, मैं उससे सहमत हूँ कि उन्होंने जो कहा, उसकी व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है, उन्होंने कहा- मैं बांग्लादेश को प्रधानमंत्री मोदी पर छोड़ रहा हूँ और यह उन पर निर्भर करता है। इस मामले पर मैं कुछ नहीं कहने जा रहा हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि यही निष्कर्ष है। भारत वापस आने के लिए विमान पकड़ने से पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि राष्ट्रपति ट्रम्प और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बांग्लादेश पर चर्चा हुई थी और हमने बांग्लादेश की स्थिति के बारे में अपनी चिंताओं से अवगत कराया है। हमें निश्चित रूप से उम्मीद है कि हालात बेहतर हो जाएंगे।

स्पष्ट रूप से, भारत और अमेरिका के बीच, यहां तक कि बांग्लादेश पर भी, विचारकों की बैठक है। आने वाले दिनों में होने वाली घटनाओं की हम प्रतीक्षा करेंगे। इसके साथ ही मैं आज के पैनल चर्चा को समाप्त करती हूँ। मैं आप सबी का यहाँ आने के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं पैनल के सदस्यों- प्रोफेसर संजय भारद्वाज, डॉ. स्मृति पटनायक और सुश्री सोहिनी बोस को भी धन्यवाद देती हूँ। आप सब का दिन शुभ हो। धन्यवाद।

ध्रुबज्योति भट्टाचार्य: कहने की कोई जरूरत ही नहीं है कि आज की पैनल चर्चा बहुत दिलचस्प थी। आईसीडब्ल्यूए की ओर से, मैं इस अवसर पर प्रतिष्ठित अध्यक्ष और पैनल में शामिल सदस्यों के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगा। हमारे सभी श्रोताओं को मेरा विशेष धन्यवाद। आईसीडब्ल्यूए के शोध कार्य, आयोजनों, आउटरीच कार्यक्रमों और प्रकाशनों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब और फेसबुक के सोशल मीडिया हैंडल देखें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत- बहुत धन्यवाद। कृपया उपकक्ष में हमारे साथ चाय का आनंद लें। धन्यवाद।